श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी. पी. वत्स (सेवानिवृत्त): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्रीमती सम्पतिया उइके (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करता हूं।

Revival of sugar mill in Motihari, Bihar

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान मोतीहारी में वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इसका प्रमुख कारण मिल में लगी मशीनरी का पुराना हो जाना एवं नई मशीनरी को लगाने हेतु पर्याप्त फंड का उपलब्ध नहीं हो पाना है। इस चीनी मिल के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप वहां पर कार्यरत स्टाफ एवं मजदूर तथा उन पर आश्रित परिवारों के सामने रोजी-रोटी का बड़ा संकट पैदा हो गया है। 2014 में, चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां गए थे।

श्री सभापति : नहीं, आप केवल अपने विषय के संबंध में बताइए। No mention-about political things. यह ज़ीरो ऑवर है।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : सर, मैंने लिख कर दिया है, मैं उसी विषय पर बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : ज़ीरो ऑवर में लिख कर देने का सवाल नहीं है, वह तो Special Mention में होता है। ज़ीरो ऑवर में केवल सरकार का विशेष ध्यान दिलाने के लिए बोला जाता है।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : ठीक है, सर।

वहां कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है। 2017 में दो व्यक्तियों, नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा ने प्रशासन की नज़र में वहां ये सब बातें लाई थीं, जिसके बाद इन दोनों ने आत्मदाह कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का ध्यान उधर नहीं जा रहा है। अभी कुछ लोगों को जानकारी मिली है एवं ऐसा ज्ञात हुआ कि इस चीनी मिल की उपयोगी ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज बनाने हेतु एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। इससे साफ-साफ यही संकेत मिलता है कि भविष्य में यह चीनी मिल कभी प्रारम्भ नहीं हो सकेगी, जिसके परिणामस्वरूप गन्ना किसानों के सामने हमेशा के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा।

गन्ना किसानों के भविष्य में दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि भारत सरकार को किसी भी प्रकार से इस चीनी मिल को प्रारंभ किए जाने की पहल करनी चाहिए, ताकि गन्ना

[श्री अखिलेश प्रसाद सिंह]

किसानों एवं उन पर आश्रित लोगों को बदहाली से बचाया जा सके। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा कर, शीघ्रातिशीघ्र उपरोक्त चीनी मिल को पुन: प्रारम्भ किए जाने हेतु उचित प्रयास किए जाएं, जिससे गन्ना किसानों को बदहाली से बचाया जा सके।

श्री अहमद अशफाक करीम (बिहार): सर, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

†**جناب احمد اشفاق کریم (بہار):** سر، میں مانینے سدسنیے کے ذریعے اٹھائے گئے موضوع سے خود کو سمبدّ کرتا ہوں۔

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : सर, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Need for formulating a law to check closure of schemes/projects due to change of Government in States

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तात्कालिक विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, लोकतंत्र में सरकारें आती-जाती रहती हैं, यह स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी सरकार को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग हो।

मान्यवर, कल ही एक समाचार आया कि महाराष्ट्र में सरकार परिवर्तन होने के बाद, 65,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं, जो वहां संचालित थीं, उन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, केवल महाराष्ट्र ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में इस तरह की परियोजनाएं हैं, जो पिछली सरकारों के समय में स्वीकृत हुईं, लेकिन आज बंद पड़ी हैं। इन परियोजनाओं पर लाखों-करोड़ रुपया...**(व्यवधान)**...

श्री संजय राउत : सर, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : वे कह रहे हैं कि ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। It has been taken note of.

डा. अशोक बाजपेयी : मान्यवर, ऐसी तमाम परियोजनाओं पर देश की जनता का लाखों-करोड़ रुपया व्यय हो चुका है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के कारण वे परियोजनाएं अधूरी छोड़ दी गईं और आज स्थिति यह है कि उनकी cost escalation बढ़ती जा रही है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से जो रोज़गार सृजित होता, वह सृजित नहीं हो पा रहा है। यह विकास के रास्ते में बाधा है। कोई भी परियोजना स्वीकृत करने से पहले सरकारें उसका गंभीर परीक्षण करती हैं। पहले उसका विधिक परीक्षण होता है, फिर तकनीकी परीक्षण होता है, उसके बाद वित्तीय स्वीकृति जारी

†Transliteration in Urdu Script.